15.05 hrs.

RESOLUTION *RE.* STEPS TO IMPROVE ECONOMY AND TO REDUCE INEQUALITIES OF INCOME, ETC.—*contd.*

MR DEPUTY-SPEAKER: Now we take up further consideration of the resolution moved by Shri Kanwar Lal Gupta on the 9th December, 1977.

Shri Gupta.

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रस्ताव किसी पार्टी का प्रस्ताव नहीं है, मेरा यह प्रस्ताव किसी दल का प्रस्ताव नहीं है । यह राष्ट्र की जो सब से बड़ी समस्या है वह सुलझाई जा सकती है यदि सभी लोग मिल कर के काम करें । मैं समझता हूं इस प्रस्ताव में जहां मेरी पार्टी साथ देगी वहां विरोध पक्ष के लोग भी इससे सहमत होंगे । इस सदन का शायद ही कोई एसा सदस्य होगा जो इसका विरोध करेगा या इससे अपना मतभेद रखेगा । आपको याद होगा सितंबर, 1963 में डा० लोहिया ने इस सदन में यह सवाल उठाया था जब उन्होंने कहा था कि भारत के 21 करोड़ लोगों की रोजाना आय तीन आने है । उस समय के प्रधान मंत्री जो थे उन्होंने कहा था कि यह आंकड़े गलत हैं और योजना मंत्री ने दूसरे आंकड़े बताये थे लेकिन डा० लोहिया ने अपने तथ्यों और आंकड़ों द्वारा सिद्ध कर दिया था कि भारत की 40 परसेंट आबादी की औसत आय तीन आना रोज है । डा० लोहिया ने यह प्रस्ताव रख करके इस देश की बहुत बड़ी सेवा की थी। मैं इस सदन और देश की तरफ से उन्होंने जो ऐसा प्रस्ताव रखा था, उन के आदर में अपना सिर नतमस्तक करता हूं क्योंकि उन्होंने भारत की ऐसी जनता की आवाज यहां पर उठाई थी जो कि बाहर नहीं बोलती । उन्होंने एसे लोगों की आवाज उठाई थी जिन की अखबार में चर्चा नहीं होती । आज मैं कह सकता हूं कि हमारे देश में लगभग बीस करोड़ लोग ऐसे हैं, 62 करोड़ लोगों में से, जिनकी आय 25 पैसा रोजाना से ज्यादा नहीं है । कोई अखबार, कोई अर्थशास्त्री, कोई एकोनामिस्ट, कोई सरकार और कोई दल उनकी बात के बारे में चर्चा नहीं करता । जनरल बातें होती हैं कि खेती का उत्पादन बढ़ना चाहिए, इण्डस्ट्रीज का उत्पादन बढ़ना चाहिए,—सरकारी कर्मचारी का भत्ता बढ़ना चाहिए, मजदूरों का भत्ता बढ़ना चाहिए—मैं उस के खिलाफ नहीं हूं लेकिन ऐसे लोग भी तो इस देश में हैं जो आर्गेनाइज्ड लेबर नहीं हैं, किसी यूनियन के मेम्बर नहीं हैं, जो फार्मर भी नहीं हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस में भी नहीं हैं, जो व्यापारी या इंडस्ट्रियलिस्ट भी नहीं हैं तो उन लोगों की आवाज को कौन उठायेगा ? आज हमारे देश में चारों तरफ रेत या रेगिस्तान है और कहीं कहीं पर देश में आईलैंड दिखाई देते हैं यह गरीबी का रेगिस्तान है लेकिन बीच में कहीं आईलैंड दिखाई देते हैं । आप अशोका होटल में जाय, आप ओबेराय में जाये या शहरों में जहां नाच-गाने होते हैं वहां पर आप जाय तो आप को थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा कि यह देश भी बहुत सम्पन्न हो गया है लेकिन अगर आप बिहार में जायें, कबायली इलाकों में जायें, मिजोरम और नागालैंड में जायें या मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में जायें तो देखेंगे कि लगातार तीस साल की आजादी के बाद भी जब कि उसकी बागडोर हमारे हाथ में है, उसकी किस्मत बनाने वाले हम हैं फिर भी महिलायें आज नंगी फिरती हैं । आज भी उन को खाने के लिए रोटी नहीं मिलती । आज भी लोग गोबर से अनाज चुग चुग कर खाते हैं और पहनने के लिए उन के पास कपड़ा नहीं है । रहने के लिए मकान का तो सवाल ही पैदा

श्री कंवर लाल गुप्त]

पैदा नहीं होता । तो ऐसे बीस करोड़ लोगों की आवाज कौन उठायेगा ?

15.07 hrs.

[SHRI DHIRENDRANATH BASU *in the Chair*]

इस देश के विधान ने प्रजातंत्र दिया है, पोलिटिकल इक्वेलिटी भी दे दी है कि हर आदमी का एक वोट है चाहे वह प्रधान मंत्री हों, टाटा-बिड़ला हों या कोई गरीब आदमी हो जो कि झोंपड़ी में रहता है—हरएक का समान वोट होगा। लेकिन क्या पोलिटीकल इक्वेलिटी से देश की समस्यायें हल हो जायंगी, क्या पोलिटिकल इक्वेलिटी से देश के अन्दर प्रजातन्त्र रह सकता है ? जब तक गरीबी और भुखमरी रहेगी, पेट में आग जलती रहेगी, देश के अन्दर आग बुझ नहीं सकती है, देश में भी जलती रहेगी, उस को कोई रोक नहीं सकता । पोलिटिकल स्टेबिलिटी लानी लानी है तो आप को इकोनामिक-इक्वेलिटी भी लानी होगी। जब तक आर्थिक व्यवस्था ऐसी नहीं होती, तब तक इकानामिक इक्वैलिटी नहीं आती, तब तक प्रजातंत्र नहीं रह सकता, उस के लिये हमेशा खतरा बना रहेगा ।

आज हड़तालें हो रही हैं, तरह-तरह की मांगें हो रही हैं। मैं हड़तालों के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन जो भूखा है, वह क्या नहीं करेगा । तुलसीदारस जी ने कहा है—खाली पेट भजन भी नहीं हो सकता है, खाली पेटवाले के लिये कोई भगवान नहीं है । स्वामी विवेकानन्द ने भी कहा है—यदि भगवान को याद करना है, तो पेट भरा हुआ होना चाहिये । अगर प्रजातंत्र रखना है तो लोगों को खाना मिलना चाहिये, एसेंशियल-कमाडिटीज मिलनी चाहिये । आज मेरा सदन के सामने और सरकार के सामने यह सवाल है कि क्या उन बीस करोड़ लोगों के लिये आप इस बात की गारन्टी दे सकते हैं कि चार साल या पांच साल तक जो आप की अवधि है, उस अवधि में उन को आप आवश्यक वस्तुयें देंगे ? यदि आप देंगे, तो क्या देंगे, कैसे देंगे?

आप कहते हैं कि हम ने पीने के पानी के लिये 40 करोड़ रुपये का प्राविजन किया है, सड़कों के लिये पर्याप्त धन रखा है, राशन की दुकानें खोल दीं, लेकिन जिस चीज की मैं बात करता हूं, जिन लोगों के लिये मैं आज बोल रहा हूं—वहां राशन की दुकानें नहीं हैं, वहां सड़कें नहीं बनती हैं, वहां पीने का पानी भी नहीं है। सभापति महोदय, राशन सिस्टम में 50 करोड़ रुपये की सबसिडी सरकार हर साल देती है, फर्टिलाइजर के लिए 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है, इलैक्ट्रिसिटी में सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान होता है, इसी तरह जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको सैकड़ों करोड़ रुपए का इन्सेन्टिव देते हैं। सब मिला कर डेढ़ या दो हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी इन्सेन्टिव और लास सरकार बरदाश्त करती है। लेकिन इसका लाभ किसको होता है ? इसका लाभ ऊपर के कुछ लोगों को होता है। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बड़ा किसान है—ये सब लाभ इन लोगों को होता है, उन 20 करोड़ पिछड़े इन्सानों को नहीं होता है, इसलिए कि उनकी आवाज खुलती नहीं है, वे अपना पेट मसोस कर दम तोड़ देते हैं। अखबारों में भी उनकी चर्चा नहीं होती, वे भूख से मर गए या किसी बीमारी में मर गए – किसी को पता नहीं चलता।

मैं इस सवाल में किसी तरह की पोलिटिक्स को नहीं लाना चाहता। मैं यह

मानता हूं कि यह सरकार जो केवल 9 महीने पहले बनी है, ग्राज उस का जवाब नहीं दे सकती। जिस पार्टी ने 30 साल तक यहां लगातार राज्य किया, शायद दुनिया के इतिहास में किसी भी देश में ऐसा नहीं हुग्रा, जहां बगैर किसी बाधा के तीस साल तक किसी ने राज्य किया हो, केवल इसी पार्टी ने इस देश में राज्य किया, लेकिन पिछले तीस सालों का उसका पिछला इतिहास यह है कि बीस करोड़ ग्रादमियों की ग्रामदनी केवल 25 पैसे रोज है। मैं ग्राप से जवाब नहीं मांगता, लेकिन मैं यह जरूर मांगता हूं कि इन्होंने जो कुछ किया, वह ग्राप के सामने है, लेकिन ग्रब ग्राप क्या करना चाहते हैं? ग्राप पांच सालों में क्या क्या योजनायें लायेंगे। इन लोगों के लिए सड़क, पानी, कपड़ा उपलब्ध करेंगे तो मैं यह कहूंगा कि ये सब चीजें उन लोगों के लिए नहीं है जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो पहाड़ों पर रहते हैं उनके लिए ग्रापने कोई चीज बनाई है क्या? मेरे पास ग्रांकड़े हैं जो सरकार ने दिए हैं। एक तरफ तो यह चीज है ग्रौर दूसरी तरफ बिग बिजिनैस हाउसिस हैं जिनके बारे में मंत्री महोदय ने परसों तरसों ही सदन में जवाब दिया है। इनके एसेट्स को ग्राप देखें कि 1951 में जो ये थे उनके मुकाबले में ग्राज कितने हो गए हैं।

The figure was Rs. 594 crores in 1951. It went up to Rs. 2759 crores in 1971 and to Rs. 3717 crores in 1975-76.

1951 से ले कर 1975 तक 24-25 साल में सात गुना उनके एसेट्स बढ़ गए हैं। जब पहले डा० लोहिया ने इन लोगों का सवाल उठाया था ग्रगर परचेजिंग कैपेसेटी का हिसाब लगाया जाए तो पहले से ग्रब उनकी यह कम हो गई है। मेरा सुझाव है कि ग्राप ग्रलग से सैस या टैक्स या सरचार्ज हर एक पर लगा दें। जो बड़ा फार्मर है, बड़ा सलेरी क्लास का ग्रादमी है, ट्रेडर है, इंडस्ट्रिलिस्ट है, जिस किसी की एक हजार या पांच सौ रुपए से ऊपर ग्रामदनी है उस पर ग्राप स्पेशल टैक्स लगा सकते हैं ग्रौर इस तरह से ग्राप एक साल में एक हजार करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। थोड़ी बहुत माइनर एडजस्टमैंट्स हीयर एंड देयर वुड नाट डू। एक ग्रादमी जो एक या दो कारें रखता है उसकी हर कार के पीछे लगाएं, जो भी लग्जरी ग्राइटम्स हैं उनकी परिभाषा भी उनके हिसाब से ग्रापको देखनी होगी, जो मोटर साइक्ल रखता है, एयर कंडीशनर रखता है, कूलर रखता है, फीजर रखता है उन सब पर ग्राप इस टैक्स को लगाएं। एक हजार करोड़ रुपया साल का इस तरह से ग्राप इकट्ठा करें ग्रौर यह राशि ग्राप इन लोगों की बहबूदी के लिए लगाएं। एक ग्रलग से इसकी योजना बननी चाहिए। ग्रौर उस इलाके में यह खर्च होनी चाहिए। ऐसा ग्राप ने किया तभी कुछ हो सकेगा। जैसे पहले सरकार कहानियां बनाया करती थी वही कहानियां ग्राप भी बनाते हैं, ऐसा कहा जाएगा। ग्राप कभी यही कह देंगे कि हमने पानी इतना कर दिया है, सड़कें इतनी बना दी हैं, सबसिडी दे दी है ग्रौर इससे कुछ नहीं होगा। स्पेशल टैक्स ग्रौर इन लोगों के लिए हों। जब ग्राप जवाब दें तो इस का उत्तर ग्राप मुझे ग्रवश्य दें कि ग्राप यह टैक्स लगायेंगे या नहीं। हर एक पर यह लगना चाहिये ताकि पांच साल में ग्राप को पांच हजार करोड़ मिल जाएं जो कि इन लोगों पर खर्च हों। इस से उन का लेवेल कुछ ऊपर ग्रा सकेगा। ग्राज कोई लेवेल ही नहीं है।

हम पांच योजनाएं बना चुके हैं। इनका ग्रसर क्या हुग्रा है। चार योजनाग्रों में हम पच्चीस हजार करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं। इतना खर्च करने के बाद भी क्या लाभ हुग्रा है? इसकी इको-

[श्री कंवर लाल गुप्त]

नोमिक्स को ग्राप दख तो ग्रापको पता चलेगा कि जो गरीब था वह ग्रौर गरीब हो गया है ग्रौर जो ग्रमीर था वह ग्रौर ग्रमीर हो गया है (व्यवधान) ।

सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि जो पंचवर्षीय योजनायें बनीं उन से मैं यह नहीं कहता कि देश को लाभ नहीं हुग्रा । देश ग्रागे बढ़ा है, उद्योग ग्रौर खेती बढ़ी है । लेकिन इन 20 करोड़ लोगों का क्या हुग्रा, इनके केस में कोई प्रगति हुई क्या ? मैं कहता हूं कि नहीं हुई, ग्रौर ग्रगर हुई भी तो बहुत मामली । ग्रौर इस से यह नतीजा निकला कि गरीब गरीब होता गया ग्रौर ग्रमीर ग्रमीर होता गया । ग्रब यह डिसपरिटीज़ हो गई । डिसपरिटीज से इरीटेन्ट्स पैदा होंगे, वायलेंस होगी ग्रौर फिर क्लेश होगा ग्रौर एक एसी हालत ग्राजायेगी जो देश में प्रजातंत्र खतरे में पड़ जायगा । मैं समझता हूं कि जो रोलिंग प्लान बनाने की योजना है वह एक ग्रच्छा ग्राईडिया है ताकि हर साल उस पर विचार किया जा सके कहां तक हम ग्रागे गये हैं, किस क्षेत्र में ग्रागे गये हैं, ग्रौर किस में हमें ग्रागे जाना है ग्रौर उस के बाद दोबारा उस पर फ़ारमुलेशन हो जाय । मैं समझता हूं कि ग्रभी तक जो तरीका रहा है प्लान बनाने का वह ज्यादा तसल्लीबख्श नहीं रहा । तो यह सारी समस्यायें हैं । ग्रब इस का समाधान क्या होगा ? एक तरफ़ तो भूखा ग्रादमी है ग्रौर दूसरी तरफ यह है कि जो ग्रमीर ग्रादमी है वह ग्रपनी ग्रमीरी की नुमाइश करता है । उस से गरीब को ग्रौर ज्यादा पिंच होता है । तो मैंने इस में यह भी कहा है कि जो खर्चा हो उस पर भी सीलिंग लगनी चाहिये । ग्राप को सभापति जी, मालूम होगा कि उधर कानपुर में मिल के मजदूरों पर गोली चली 10, 12 लोग मारे गये ग्रौर उसी मिल मालिक के यहां दिल्ली में शादी हो रही थी । वहां पर 7, 8 लाख रु० खर्च किया गया । मेरी ज्यादा उम्र नहीं है, माननीय गौरी शंकर मुझसे उम्र में बड़ हैं, लेकिन पहले कितने भी लोग ग्रमीर हों लेकिन ग्रमीर होने के बाद भी उन के रहन सहन से यह पता नहीं लग सकता था कि कौन ग्रमीर है कौन गरीब है । वह ग्रपने पैसे की नुमाइश नहीं करते थे । मैंने पहले भी बताया था कि मैं सुबह सैर करने जाता हूं, सभापति जी, हमारे पड़ोस में 5, 7 मकान छोड़ कर एक ग्रादमी रहते हैं, उन की कोठी है, माननीय तिवारी जी जानते होंगे, उन के 7, 8 कुत्ते होते हैं, चार नौकर रख हुए हैं ग्रौर उन कुत्तों पर उनका कम से कम 2, 3 हजार रु० महीना खर्च होता है । ग्रब ग्राप बताइये कि एक तरफ़ तो यह नुमायश है इसको खत्म होना चाहिये ग्रौर सरकार को उस दिशा में कदम उठाना चाहिये । पहले ग्रापने एक्सपेंडिचर टैक्स लगाया था लेकिन उनका कोई ज्यादा ग्रसर नहीं हुग्रा । तो मैं यह चाहता हूं कि सरकार इस चीज के ऊपर रोक लगाये । किस तरह से हो मेरे ध्यान में कोई तजबीज नहीं है, कोई कानक्रीट प्रापोज़ल नहीं है । लेकिन मैं यह जरूर चाहूंगा कि इस के बारे में विचार किया जाये कि कोई भी ग्रादमी ग्रपनी रिच नैस ग्रौर पैसे की एग्ज़ीबीशन न कर पाये । इस के लिये सरकार को कोई योजना ग्रवश्य ही बनानी चाहिये ताकि गरीब के दिल में पिंच तो न हो कि मैं भूखा भी हूं ग्रौर मेरी बइज्जती चौराहे पर हो रही है ।

सभापति महोदय, हमारे देश में 20 हजार लोग रोज ग्रन-एम्प्लायड होते हैं । जनता पार्टी की कमिटमैंट है कि 10 साल में हरेक

को रोजगार देंगे। लेकिन कोई फ़ेज़ प्रोग्राम तो बनाना चाहिए कि एक साल में कितनों को, 2 साल में कितनों को रोजगार देंगे। मैं मानता हूं कि पहले साल मशीनरी ज्यादा तेज नहीं हो सकती, लेकिन कुछ तो टारगैट बताइए। श्री सुब्रह्मण्यम जी ने भी 1976 में कहा था कि हम एक साल में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन एक को भी रोजगार नहीं दिया। तो जो आपका कहना है, उसको कैसे पूरा कर रहे हैं और कितना एक साल में पूरा किया, जब तक आप यह नहीं बतायेंगे, तब तक लोग हम पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि जनता पार्टी इस चीज में विश्वास करती है कि जो वह कहती है, वह करती है और हमने कर के दिखाया भी है। आगे भी मुझे विश्वास है कि 10 साल में हम करेंगे, लेकिन मंत्री महोदय इस चीज को स्पष्ट करें कि हर साल कितने लोगों को वह एम्पलायमेंट देंगे।

अभी हमारे माननीय मंत्री ने इंडस्ट्रियल पालिसी रखी, उसके बारे में तो विचार होगा, लेकिन वह एक बहुत बड़ा कदम है कि डिस्पैरिटी दूर हो। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि आज तक हमेशा कुछ थोड़ा इधर उधर एडजस्टमैंट कर के वही 1956 का प्रस्ताव किया गया, लेकिन अब उन्होंने कुछ डैविएशन किया है। लेकिन डैविएशन प्रस्ताव से नहीं, इम्पलीमैंटेशन से पता लगेगा और जब तक वह नहीं होगा कुछ नहीं हो सकेगा। मुझे आशा है कि जिस तरह के डायनेमिक मंत्री वह हैं, जरूर पूरा कर के वह बताएंगे।

एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि डिस्पैरिटीज दूर करने के लिए जनता पार्टी की कमिटमैंट है। जनता पार्टी ने यह कहा है कि जो प्रापर्टी का फण्डामेंटल राइट है वह नहीं रहना चाहिए, वह कानून के जरिये से होना चाहिए। मैं यह मांग करता हूं कि अगर प्रापर्टी का फण्डामेंटल राइट रहा तो आज जो 20 करोड़ लोगों को मकान, रोटी और कपड़ा देना है, नहीं दे सकेंगे, संभव नहीं है। अगर किसी का महल है और बराबर में झोंपड़ी है तो उस झोंपड़ी पर कम से कम छप्पर जरूर डलना चाहिए और जब तक वह छप्पर नहीं पड़ेगा तब तक डिस्पैरिटी दूर नहीं होगी। फण्डामेंटल राइट आफ प्रापर्टी तो खत्म करिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इसे तो खत्म कर दिया लेकिन गरीबों को कोई लाभ न मिले। उनको भी लाभ मिलना चाहिए।

आपको याद होगा कि लेटेस्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा है कि बेसिक फीचर्स विधान में रहने चाहिए। उनको यह पार्लियामेंट बदल नहीं सकती और उस बेसिक फीचर में प्रापर्टी का फण्डामेंटल राइट इन्क्लूड नहीं था। मैं यह मांग करूंगा कि इस पर विचार होना चाहिए और अगले सेशन में इस पर विचार और कार्यवाही होनी चाहिए।

राइट टू वर्क को कम-से-कम सरकार प्रिंसिपल में तो जरूर मान ले। मैं मानता हूं कि अभी दिक्कत हैं, अभी शायद इम्पलीमैंटेशन नहीं कर सकेंगे, आपकी व्यावहारिक कठिनाइयां हैं। लेकिन एक प्रिंसिपल जरूर माना जाना चाहिए कि राइट टू वर्क यानी हरेक आदमी को काम का अधिकार मिलेगा। तभी हम समझेंगे कि जनता पार्टी सही मानों में कुछ करना चाहती है।

जैसा कि मैंने पहले कहा है, वह किसी एक पोलीटिकल पार्टी या गवर्नमेंट का सवाल नहीं है। केवल गवर्नमेंट के द्वारा यह काम नहीं होगा। चाहे किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, और चाहे कितने भी कानून बनाये जायें, लेकिन जब तक जनता जागृत नहीं होगी, जब तक ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलि-

[श्री कंवर लाल गुप्ता]

स्ट्स में यह अनुभूति पैदा नहीं होगी कि हमारे जो भाई भूखों मर रहे हैं, उन के लिए भी हमें कुछ करना है, और कुछ तकलीफ उठा कर भी इस के लिए कुछ काण्ट्रीब्यूशन करना है, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। यह जाग्रति पैदा करने के लिए सरकार को एक राइट टाइप आफ़ एजूकेशन देनी चाहिए। वालण्ट्री आर्गनाइजेशन्ज़ को भी इस काम में शामिल करना चाहिए, और देश में एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए, जिस के जरिये इन दबे-पिसे, मूक लोगों को काम मिले और कम से कम जीवन के एसेंशल आइटम्ज तो मिल सकें।

मैं चाहता हूं कि इस सवाल पर सरकार विपक्ष से भी बातचीत करे। मैंने बीस करोड़ लोगों के लिए जो स्पेशल टैक्स का सुझाव दिया है, उस के बारे में और दूसरे स्टेप्स के बारे में सब का कोआपरेशन लिया जाये और एक नैशनल कानसेन्सस डेवेलप किया जाये कि किस तरह देश आगे बढ़ सकता है, किस तरह डिस्पैरिटीज कम हो सकती हैं, कैसे एग्जहिबिशन आफ़ रिचनैस खत्म हो सकती है। अगर सब पार्टियों के सहयोग से इस के लिए एक उचित सामाजिक दृष्टिकोण पैदा किया जाये, तो एक दिन जरूर आयेगा, जब महात्मा गांधी का यह सपना साकार होगा कि इस देश में रामराज्य स्थापित हो। अगर डिसपैरिटीज कायम रहीं, तो प्रजातंत्र भी खत्म हो जायेगा—प्रजातंत्र भी नहीं रहेगा।

MR. CHAIRMAN: Motion moved :

"This House urges upon the Government to take effective steps to improve the economy of the country and to reduce the inequalities of income, wealth and personal consumption."

There are some Amendments to be moved.

SHRI S. S. DAS (Sitamarhi): I beg to move:

That in the resolution,—

add at the end—

"and the loot of the rural people by the urban elite and organised pressure groups be curbed. The House further directs the Government to basically restructure the outmoded, exploitative and elitist state—capitalist model of the Indian society and the Indian State." (1)

MR. CHAIRMAN: Shri Brij Bhushan Tiwari—not present;

Shri Chandra Shekhar Singh not present.

SHRI GAURI SHANKAR RAI: (Ghazipur) I beg to move:

That in the resolution. —

for "wealth and personal Consumption"

substitute—

"Pay, wealth and fix a Ceiling on the expenditure" (4)

MR. CHAIRMAN: Shri Ram Dhari Shastri——not Present.

श्री श्याम सुन्दर दास : सभापति महोदय, मैं भावानात्मक स्तर पर श्री कंवर लाल गुप्त के प्रस्ताव के साथ हूं, लेकिन उस प्रस्ताव में जो आकांक्षायें व्यक्त की गई हैं, वे ऐसी आकांक्षायें हैं, जिन के बारे में अभी तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई मतभेद नहीं रहा है। मैं अपने संशोधन के द्वारा उन के प्रस्ताव में कुछ बातें जोड़ देना चाहता हूं, ताकि सरकार के सामने केवल इतना ही न रहे कि विषमताओं को कम करना हैं और रोजगार के अवसर बढ़ाने हैं, बल्कि इस बात का भी विश्लेषण किया जाये कि क्या कारण है कि इस के बावजूद कि पिछली सत्तारूढ़ पार्टी इन्हीं लक्ष्यों को मानती रही है, लेकिन पहली पंच-वर्षीय योजना से ले कर आज तक गांव गरीब होते चले गये हैं और हिन्दुस्तान के मानचित्र में कुछ शहर या औद्योगिक केन्द्र सत्ता, सम्पन्नता और वैभव के केन्द्र बन कर रह गये हैं। मार्च, 1977 में सत्ता का परिवर्तन हुआ, और इस सम्बन्ध में सरकार को कुछ बातें स्मरण रखनी चाहिए। मेरे कहने का यह आशय नहीं कि सरकार उन चीजों को भूलती जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस प्रकार हम लोगों ने आशा की थी, सरकार को चूंकि पिछला बजट ऐसे समय में बनाना पड़ा कि सरकार उस के अनुरूप महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं कर सकी। इसलिए अभी समय है कि जब कि जनता पार्टी की कार्य समिति ने जो फैसला किया है या हमारे चुनाव घोषणा-पत्र

में जिस तरह के फैसले हैं उन दिशाओं में सरकार को कुछ ठोस बातें करनी चाहिएं। द्वितीय महायुद्ध के बाद जितने देश उप-निवेशवाद के चंगुल से मुक्त हुए उन में हिन्दुस्तान का एक प्रमुख स्थान था। यों रूस की क्रान्ति के बाद बाजाप्ता राज्य के द्वारा नियोजनात्मक विकास से राज्य का आर्थिक ढांचा मजबूत किया जा सकता है ऐसी एक कल्पना आई और ऐसी कल्पना जहां तक आर्थिक क्षेत्र है बहुत मामलों में सफल भी हुई। लेकिन जनतांत्रिक ढांचे के अंदर योजना के द्वारा हम देश का आर्थिक विकास करेंगे, बेकारी दूर करेंगे, प्राइसेस का स्तर एक प्रकार का बना रहेगा या विकास की दर के साथ चाहे मूल्य के स्तर में थोड़ी वृद्धि होगी, ऐसी चीज चलाने की बात हुई। लेकिन देश का जो विकास हुआ वह गलत रास्ते पर चला गया। उत्पादन पर, बड़े उद्योगों पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा। यह सही है कि अब पहली बार लगता है कि रोजगार को केन्द्र माना जायगा, समता के साथ सम्पन्नता आ सकती है और रोजगार के द्वारा ही उत्पादन बढ़ सकता है, इन सारी बातों को सरकार मानने लगी है। लेकिन अभी तक जो सरकार की आर्थिक नीति है, मैं नहीं जानता कि इंडस्ट्रियल पालिसी की घोषणा होगी तो उस में इन सारी बातों की चर्चा होगी या नहीं होगी लेकिन अभी तक इस तरह का कोई ठोस कार्यक्रम नहीं आया है। जिस तरह से कास्मोपालिटन सेंटर्स समूचे संसार के पैमाने पर रहे, कुछ मेट्रोपोलिटन कण्ट्रीज रहे जिन्होंने अविकसित देशों को एक्सप्लायट किया ऐडवर्स ट्रेड के द्वारा, उसी तरह से एक देश के अन्दर भी उसी तरह के अनेक उपनिवेश और कुछ मेट्रो-पोलिटन सेंटर्स हैं जो समूचे देश का शोषण करते रहे हैं। माओ-त्से-तुंग ने एक बार यह नारा दिया था कि देहात को अब चाहिए कि वह शहरों की ओर बढ़े और शहरों को घेर ले। सम्पूर्ण एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के वैसे देश जो कृषि-प्रधान देश हैं वहां की राजनीति शहरी सभ्यता के साथ, शहरी राजनीति केथ केन्द्रित हो गई जहां आर्गनाइज्ड प्रेशर ग्रुप हैं चाहे वह लेबर के हों चाहे बुर्जुआ के हों लेकिन देहात में एक झूठे प्रकार के विभाजन की स्थिति वे बार बार पैदा करते रहते हैं ऐग्रीकल्चरल लेबरर्स में और फार्मर्स में लेकिन जहां प्राइस फिक्सेशन का सवाल आता है ऐग्रीकल्चरल कमोडिटीज की प्राइस और मैन्यूफैक्चर्ड आर्टिकिल्स की प्राइस में सामान्यतया देखा गया है कि उत्पादित वस्तुओं का मूल्य जिस स्तर पर एक बार चला जाता है अगर घटता भी है तो .5 परसेंट या .4 परसेंट लेकिन ऐग्रीकल्चरल कमोडिटीज में चाहे वह रा-मैटीरियल हों या सीरियल्स हों उन का प्राइस लेवेल बढ़ता है तो फिर उस को आर्टिफिशियली चाहे अमेरिका से अन्न मंगा कर या कैनाडा से रशिया से गेहूं और अन्न मंगा कर उस की प्राइस को घटा दिया जाता है। आप देखें शुगर केन का प्राइस एक और शुगर का प्राइस दूसरा है। काटन का प्राइस कम है और काटन टेक्सटाइल का प्राइस ज्यादा है। बिजली आप देते हैं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में उस का रेट बहुत कम रहता है और वही बिजली जब देहात में इरीगेशन के लिए दी जाती है तो उस का रेट बहुत ज्यादा रहता है। तो एक तरह से प्लाण्ड लूट चल रही है रूरल सेक्टर की अर्बन सेक्टर के द्वारा और इसके कारण आज हिन्दुस्तान का मजदूर वर्ग भी दो हिस्सों में बंट गया है— एक तो जो सर्टेन सेंटर्स हैं, बड़े बड़े उद्योगों के जहां केन्द्र हैं वहां जो आर्गनाइज्ड लेबर है उस को पर डे जितनी मजदूरी मिलती है, उस की तुलना खेतिहर मजदूरों से करें तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि यहां का जो मजदूर वर्ग है उस मजदूर वर्ग को भी दो हिस्सों में बांट

[श्री श्याम सुन्दर दास]

दिया गया है । और उनका शोषण चलता रहा । भारतीय राजनीति का जो सत्तारूढ़ वर्ग रहा है उसका चरित्र रहा है कि मजदूरी के मामले में, जमीन के मामले में या अनेकों दस प्रकार के सवाल उठा कर झगड़ा पैदा करें, अगर मजदूरी और जमीन के मामले में झगड़ा न हो तो जातपांत के नाम पर झगड़ा पैदा किया जाये ताकि देहातों को विभाजित करके रखा जा सके और इस प्रकार से शहरी लोगों का वर्चस्व बराबर बना रहे। इसका परिणाम यह हुआ है कि हिन्दुस्तान का आर्थिक विकास लापसाइडेड हो गया है। यहां की राजनीति कुछ मुख्यत: चुनिन्दा वर्गों के हाथ में सिमट कर रह गई है जिन्होंने अपना हित बरकरार रखा है और इस प्रकार से ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का शोषण शहरी अर्थ-व्यवस्था के द्वारा होता रहा है। जब तक इसके बारे में अर्थ मंत्री निश्चित रूप से निर्णय नहीं लेंगे तब तक रूरल एइण्डस्ट्रीज को डेवलप करना, काटज एण्डस्ट्रीज को डेवलप करना, इरीगेशन फैसिलिटीज देना सम्भव नहीं हो पायेगा। यह सारी बातें एक नारे तक ही सिमट कर रह जायेंगी और उनका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस प्रस्ताव को संशोधन के साथ स्वीकार करे और उस उस पर ईमानदारी के साथ अमल करे।

श्री गौरी शंकर राय (गाजीपुर): सभापति महोदय, माननीय कंवर लाल जी गुप्त ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें मेरा एक छोटा सा संशोधन है। इसकी अंतिम पंक्ति में है: 'Wealth and personal consumption, उसकी जगह पर जोड़ दिया जाये: 'pay, wealth and fix a ceiling on the expenditure:'

यह बहुत छोटा सा संशोधन है। मैं इस समय यहां पर सद्धांतिक प्रश्नों की लम्बी विवेचना नहीं करना चाहता क्योंकि प्रस्ताव रखने वाले भाई ने बड़ी व्याख्या कर दी है। मैं चन्द मुद्दों पर थोड़ी सी बातें कहना चाहता हूं। मैं ऐसा नहीं मानता कि आर्थिक सामाजिक परिवर्तन करने के लिए इस देश के समाज में आमूलचूल परिवर्तन करने की कल्पना किसी पक्ष की रही है या है। पहले इसकी कुछ चर्चा अवश्य होती रही है लेकिन आमूलचूल परिवर्तन करने की कल्पना कभी नहीं रही है। इस सम्बन्ध में कुछ और अधिक कहने से लाभ नहीं होगा। मैं चाहता हूं कुछ बातें निश्चित होनी चाहिए। एक तो बिना समाजवाद और ऊंची बातों को कहे हुए इनकम और वेजेज का जो फर्क है उसको कम करना होगा। आज भी उत्तर प्रदेश में एक चौकीदार पांच रुपए पाता है और राष्ट्रपति दस हजार रुपये पाते हैं। इण्डस्ट्रियल हाउसेज के जो एग्जीक्यूटिव्ज हैं वे राष्ट्रपति से भी ज्यादा पाते हैं। कुछ लोग तो ऐसी तनख्वाह पाते हैं जिसका रुपये में आप हिसाब नहीं कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव है कि आप तनख्वाहें बांध दें और परक्वीजिट्स बन्द की जायें। आज मंत्री जो तनख्वाह पाते हैं, मैं नहीं कहता कि वह ज्यादा है, आप चौगुनी तनख्वाह कर दीजिए लेकिन यह निश्चय हो जाना चाहिए कि कितनी इनकम है, कितना खर्चा है और कितना इनकम टैक्स है। इसी तरह से बड़े बड़े सरकारी अफसर हैं, पार्लमेण्ट के मेम्बर हैं उनको सुविधायें मिलती हैं, उनका आप हिसाब लगाइये। गरीब आदमी को उनके लिए सब जगह पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इस तरह का जो सुविधाप्राप्त वर्ग सरकार में बना हुआ है उसको हटना चाहिए और निश्चित रूप से

वेजेज के बीच में एक उचित अन्तर स्थापित किया जाना चाहिए । मैं नहीं कहता कि आज ही आप एक और तीन का सम्बन्ध स्थापित करवें लेकिन क्या कभी सरकार इस बात को सोचेगी या नहीं ? आमदनी और वजेज में क्या रिलेशंस होंगे, कितने गने होंग, कम से कम इस बात को सोचना चाहिए । सरकार को इस प्रकार से एक नेशनल वज पालिसी बनानी चाहिए । इण्डस्ट्रियल हाउसेज के जो एग्जीक्यूटिव हैं व एक दिन में पांच हजार खर्चा कर देते हैं, राष्ट्रपति भी इस स अधिक खर्च कर सकते हैं और वह खर्चा उचित समझा जाता है । इन सारी बातों को देख कर मिनिमम और मैक्सिमम वेजेज क्या हों, यह निश्चित करना चाहिए । एक सूखी तनख्वाह जिसको नैकेड सैलरी कहा जाता है उसमें कोई सुविधायें नहीं होती है । और एक तरफ तनख्वाह पांच सौ होती है लेकिन उसके बाद वह पांच हजार बनती है और एक जो पांच हजार पाता है उसकी कुल तनख्वाह पांच हजार बैंक में जाती है । तो यह व्हाइट कालर्ड तबका जो है, जिसमें मैं भी हूं, जो सरकार चलाते हैं, जो ब्यूरोक्रैट्स हैं, लीडर्स हैं वे ऐसा इन्तजाम लगाते हैं कि तनख्वाह छोटी मालूम हो लेकिन उसके साथ सुविधाये ज्यादा हों । देखने में तनख्वाह ज्यादा न लगे ।

मैं दोनों पक्षों के लोगों से कहना चाहता हूं– सार्वजनिक जीवन में हम बड़े आदर्शों की बात करते हैं, हम एक दूसरे पर चार्ज लगाते हैं । हम उनके ऊपर पिछले तीस सालों का चाज लगाते हैं—इस अवधि में जो क्रोम और हिपाक्रिसी हुई है, उस का कोई मुकाबला नहीं होगा । उस समय यदि कोई अखबार पढ़ता था तो समझता था कि यहां समाज ही बदल गया है, मैं उस समय की आदर्शवादिता की बात नहीं करता, लेकिन यह चाहता हूं कि देश में एक नेशनल वेज-पालिसी बने, नग्न वेतन मिले और विदाउट-पर्क्विजिट्स मिले ।

मैं एक बुनियादी बात और कहना चाहता हूं —हम आमदनी पर सीलिंग लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन खर्च पर सीलिंग लगाने की बात समझ में नहीं आती है । मैं किसी का नाम लना नहीं चाहता हूं, किसी को मेलाइन नहीं करना चाहता हूं, मैं अपने को ही लेकर कहता हूं—हम पार्लियामेंट के मेम्बर हैं, 500 रुपया हम को तनख्वाह मिलती है, 500 रुपया और नाम से मिलता है, इस तरह से हम को एक हजार रुपया मिलता है, अगर हमारा खर्च आमदनी से अधिक है तो हम को क्या कहा जाना चाहिये । मैं अपने वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं—वे बहुत अनुभवी अधिकारी भी रहे हैं—क्या आप के पास कोई ऐसा मेकेनिज्म है कि आप एक्सपेंडिचर पर सीलिंग लगा सकते हैं ? आप नम्बर दो के पैसे पर ऐश करने वालों को देख लीजिये —उनके कपड़ों को देखिये— उनक ड्राइंग रूम को देखिये—उनके पास इतना पैसा कहां से आया, यह बात समझ में नहीं आती है । आप कोई ऐसा हथियार बनाइये जिससे खर्च को नापा जा सके । आज अपने खर्च का हिसाब तो सब बना लेते हैं, दूसरों को एक्यूज करते हैं, लेकिन ठीक से झांका जाये, तो गुनाह सब के हिस्से में पड़ता है । इस लिये इस पर ईमानदारी के साथ सोचना चाहिये ।

एक बात की चर्चा पहले भी बहुत हो चुकी है—पिछले दस सालों में हमारे जितने मोनोपोली हाउसेज हैं, वे बहुत ज्यादा बढ़े हैं । वे पिछल 30 सालों में उतना नहीं बढ़े, जितना मोनोपोली कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद बढ़े हैं । पिछले पांच सालों में तो उन की हैसियत बहुत ही ज्यादा बढ़ी है । आज पुरानी बातों को छोड़ कर इस दृष्टि से देखा जाना चाहिये कि इस को कैसे रोका जा सकता है, हमारा जो आपरेशन का तरीका है,

[श्री गौरी शंकर राय]

काम करने का तरीका है, उस को बदलने की आवश्यकता है ।

इतना बड़ा प्रश्न हमारे सामने है, लेकिन समय की बहुत कमी है । कोई नई बात कहने का समय ही नहीं है, इस लिये मैं इतना ही कहूंगा कि नेशनल-वेज-पालिसी, खर्च की सीमा और वेतन के साथ बाहरी सुविधाओं को हटा कर, नंगा वेतन देने की व्यवस्था होनी चाहिये । चाहे पब्लिक सैक्टर हो या प्राइवेट सैक्टर हो—सब के वेतन को समान रूप से देखा जाये । आज आर्गनाइज्ड सैक्टर में, जैसे इंश्योरेंस मुलाजिम हैं, वे अपने हक के लिये लड़ सकते हैं, व्हाइट कालर्ड हैं, हमारे वयालार रवि भी उन के सवाल को उठा देंगे, स्टीफन साहब भी उठा देंगे और यदि हमारे पास आयेंगे तो हम भी उठा देंगे लेकिन आज जो दबा हुआ तबका है, उस की बात करने वाला कोई नहीं है, उस के लिये लड़ाई नहीं हो पाती है, इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं— हमें इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना चाहिये ताकि देश में नेशनल वेज पालिसी हो, मैकसिमम और मिनिमम रिलेशन खर्च में हो और नंगा वेतन देने की व्यवस्था होनी चाहिये ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मान्यवर, श्री कंवर लाल गुप्ता जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उस का पूरा समर्थन करता हूं । आज हमारे देश में जहां आय के अन्दर बहुत बड़ा अन्तर दिखाई देता है, वहां खर्च और पूंजी में भी बहुत अन्तर पाया जाता है और हमारी जो आज की प्रक्रिया है, जिस के अधीन हम समाज को नियंत्रित करना चाहते हैं, उस में हर धनवान आदमी प्रतिदिन अधिक धनी होता जा रहा है और गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है ।

हमारे देश के करोड़ों लोग आज ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें कि उन को सही ढंग से भोजन नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता, पढ़ाई का कोई सवाल नहीं, औषधि की कोई व्यवस्था नहीं है, रहने के लिये कोई मकान नहीं है । देश में ऐसे लोग भी हैं जिनकी पूंजी आजादी के समय में सौ करोड़ से नीचे थी आज उन की पूंजी बढ़ कर हजारों करोड़ तक पहुंच गई है, जहां इस प्रकार की व्यवस्था चल रही हो वहां पर किसी हालत में समाज में शान्ति नहीं रह सकती है । इस प्रकार से अन्तर यहां कायम रहेगा तो इस में सन्देह नहीं है कि देश में लोकतन्त्र भी खतरे में पड़ सकता है । जहां आज हम सामाजिक समानता अथवा राजनीतिक समानता की बात करते हैं वहां पर आर्थिक समानता के बारे में भी हमें सोचना चाहिये । प्रत्येक व्यक्ति को उस की आवश्यकता के अनुरूप सही साधन मिलने चाहियें, धन मिलना चाहिये । ऐसी व्यवस्था नहीं रहनी चाहिये जहां करोड़पति अरबपति बन जायें और गरीब जिस के पास पांच रुपये हैं उस का वह रुपया भी समाप्त हो जाए, वह अपनी जीवन की आवश्यक वस्तुओं को भी खरीद न सके, अपने जीवन को सही ढंग से न चला सके । जहां आप आय पर सीमा लगाएं वहां एक्सपेंडीचर अर्थात् खर्च पर भी सीलिंग आप लगाएं । उन के साथ-साथ कैपिटल पर भी लगाएं । अनियंत्रित पूंजी हमेशा ही देश के लिये घातक होगी । बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में जिन के पास साधन होंगे उन के पास ही उस अवस्था में पूंजी एकत्रित हो जाएगी और वे पूरे समाज को पूंजी के बल पर अपने दबाव में रखेंगे । आज की स्थिति ऐसी ही है । आज हमारे देश में प्रशासन तथा पूरा अखबार का जो तंत्र है जिसे स्टेट आफ जर्नलिज्म कहते हैं यह सभी उन के कब्जे में चला आ रहा है । यह जो स्थिति है अगर इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो हमारे देश में लोकतंत्र भी खतरे में पड़ सकता है ।

मौलिक अधिकार के रूप में सम्पत्ति के अधिकार का मैं विरोधी हूं । मैं नहीं चाहता कि सम्पत्ति काअधिकार एक मौलिक अधिकार बना रहे। इस के मौलिक अधिकार बने रहने के कारण हमारे देश में गरीब लोगों का शोषण हो रहा है। ऐसे लोगों का हो रहा है जो आर्थिक विपन्नता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

माननीय कंवर लाल गुप्त जी के प्रस्ताव का मैं इन शब्दों के साथ समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि जहां आय पर एक सीमा लगाई जाये वहां खर्च और पूंजी पर भी सीमा निर्धारित की जानी चाहिये ।

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): Sir, the moti n that has been moved reads as follows:

> "This House urges upon the Government to take effective steps to improve the economy of the country and to reduce the inequalities of inrome, wealth and personal consumption."

I don't think there should be any difference of opinion in regard to the second part of this resolution, to reduce the inequalities of income, wealth and personal consumption. And, I presume, the reference to the economy of the country means that we should develop the economy in such a way that these objectives, that is, reducing inequalities of income, wealth and personal consumption, are achieved.

I can only say that the steps which we are takng to improve the economy are many, and in fact, I think, we are achieving a measure of success.

Ever since the Government assumed office, it has b·en making every effort to improve the economy in order to achieve the basic aims of the policy to which it is committed, namely the elimination of poverty and destitution and establishment of a social order which assures freedom and equality to all its citizens. But the dimensions of the problems of poverty in India and complexity of the factors underlying them rule out any quick or easy solution. Failure of over two decades of planning to make any dent on poverty show that if the problem is to be tackled effe·tively, the entire strategy of the development should be reviewed and priorities re-defined and the economic policy will need to be reformulated in the light of the new strategy and priorities.

While in the short region the exigencies of the current situation is to be taken into account, the basic thrust of the economic policy both for the short as well as the land-term will depend on the approach one adopts to the strategy of development.

We have initiated steps already to read-define the priorities conformity with the new strategy of the planning. While the Fifth Plan for 1978 to 1983 is still being formulated by the reconstituted Planning Commission.... (*Interruptions*).

SHRI KANWAR LAL GUPTA: The Minister should tell us specifically the steps taken and not the policy which they frame.

MR. CHAIRMAN: Allow him to proceed.

श्री रामानन्द तिवारी (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, हम लोग यह जानना चाहते हैं, 20, 30 वर्ष का कोई सवाल नहीं है, सवाल यह है कि जनता पार्टी की सरकार 9 महीने से क्या कर रही है, और आगे क्या करेगी गरीबी को दूर करने के लिए ? उपदेश सुनने के लिए हम यहां नहीं हैं । हम जानना चाहते हैं कि गरीबी को हटाने के लिए क्या किया जा रहा है ?

SHRI H. M. PATEL: Mr. Chairman, I regret that what the hon. Members desire cannot be achieved with the speed with which they desire. They ask what have we been doing. We have been doing many things. (*Interruptions*). Please keep patience and then you may learnsomething If you do not have patience you cannot learn. What I am pointing out are facts. You have mismanaged the economy of this country for thirty years. You cannot expect us to change things overnight. It takes time.

15.02 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

Let us understand this. After all, I should have thought the hon. Members will realise this. The guidelines have been issued by the Planning Commission for the preparation of the State Plans for 1978-79 bearing in mind our basic objectives of accelerating the growth of per capita income to the maximum possible extent and to progress towards self-reliance. That is what is happening. We have to recognise that to tackle the problem of

[Shri H. M. Patel]

poverty, rooting out the problem of unemployment and underemployment, we have to emphasise the need to promote measures which would help to provide employment to a larger number of people. It has been pointed out in the guidelines that in order to attain the contemplated employment targets, taking into account the anticipated rise in the labour force, it will be necessary to ensure significant and sustained increase in the labour absorption in productive work in agriculture including processing storage, transport and distribution.......

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Ten minutes should be give to the Minister.

MR. DEPUTY-SPEAKER: At 4 O' clock we have to take up the Adjournment Motion.

SHRI H. M. PATEL: Guidelines have to be formulated in order to achieve a substantial shift in the investment target and the Central and State Governments Policies in areas of the economic policy will need to be coordinated with the Plan priorities. Since assured water supply is crucial for increasing productivity of agriculture and creation of employment, highest priority has to be given to investment in irrigation than it has been receiving so far. Funds would have to be preempted for investment in irrigation and agricultural production before allocations are made to other sectors. It is intended to bring an additional 17 million hectares of land under irrigation in the next five years. Large outlays would be needed to increase p wer generation keeping in view the potential for employment generation.

16.00 hrs.

श्री रामानन्द तिवारी : इनकम पर बोभा निर्धारित कीजिएगा कि नहीं ? यह कितने दिनों में, कम-से-कम और अधिक से अधिक, क्या कीजिएगा ?

SHRI H. M. PATEL: Hon. Members are getting impatient but they must know that we have appointed a study group on this question of wages and incomes policy with a view to evolve a national wage policy, which I think the mover of this resolution desired. The necessity for appointing such a study group arose because many distortions had come into the economy; in the organised labour for instance, there are groups at high levels of wages; there are others who are at the medium level.

MR. DEPUTY-SPEAKER: According to our rules, we have to take up the adjournment motion.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will you abolish the fundamental rights to property?....(*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: We take up other business. Shri Samar Ghua.

SHRI SAMAR GUHA (Contai): I beg to move:

"That the further discussion on the resolution regarding steps to improve the economy and reducing inequalities of income, etc. moved by Shri Kanwar Lal Gupta on the 9th December, 1977, be adjourned to the next day allotted to the Private Members' Resolutions in the next session and the provisions of sub-rule (I) of Rule 30 and the proviso to Rule 29 be suspended in their application to this resolution to enable the resolution to be set down in the List of Business wothout ballot, as the first item therein."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the further discussion on the resolution regarding steps to improve the economy and reducing inequalities of income etc, moved by Shri Kanwar Lal Gupta on the 9th December, 1977, be adjourned to the next day allotted to the Private Member's Resolutions in the next session and the provisions of sub-rule (1) of Rule 30 and the proviso to Rule 29 be suspended in their application to this resolution to enable the resolution to be set down in the List of Business without ballot, as the first item therein."

The motion was adopted

16.03 hrs.

RESOLUTION *RE.* REPEAL OF CONSTITUTION (FORTY-SECOND AMENDMENT) ACT AND WITHDRAWAL OF MISA

SHRI SAMAR GUHA (Contai): I begto move:

"This house recommends to the Government to redeem its sacred pledge, made to the people on the historic occasion of the last Lok Sabha Election, by forthwith repealing the Constitution (Forty-second Amendment) Act, which was passed by Parliament under a